

संख्या: ३२९३/xviii(ii)/2013-1(57)/2012 टी०सी०

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुमाग-2

देहरादून: दिनांक ३० अक्टूबर, 2013

विषय:- सामाजिक संस्था अजीम प्रेम जी फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट, बैंगलोर को जनपद देहरादून के ग्राम आमवाला तरला परगना परवादून में निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना हेतु कुल 0.4046 है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-1053/12-ए-89(2011-2014) डी०एल०आर०सी०

दि०-०३.१०.२०१३ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सामाजिक संस्था अजीम प्रेम जी फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट, बैंगलोर को जनपद देहरादून के ग्राम आमवाला तरला परगना पदवादून में निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना हेतु कुल 0.4046 है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15.01.2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता द्वारा क्य की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये

अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

3— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6— संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

7— किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

8— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

10— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

- 11— प्रश्नगत प्रयोजन की पूर्ति के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सम्बन्धित मानकों/शासनादेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12— इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना के मानचित्र की स्वीकृति विधिवत् सम्बन्धित प्राधिकरण से करायी जानी आवश्यक होगी।
- 13— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

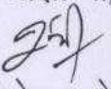
भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृष्ठ सं-३२९३/सम्बिन्दित 2013

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— श्री अनंत गंगोला, राज्य प्रमुख अजीम प्रेम जी फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट, 26 बलबीर रोड, देहरादून।
- 6— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।